Textile Department Scheme for Production of blended Handloom Fabrics

1256. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the working group set up by the Textile Department has submitted a comprehensive scheme for production of blended handloom fabrics in selected states;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) when it will be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

जांच आयोग अधिनियम मे संशोधन का प्रस्ताव

1257. **श्री अघन सिंह ठाकुर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जांच आयोग अधिनियम में इस दृष्टि से संशोधन करने का है कि जांच आयोग के विरुद्ध आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार जांच आयोग को मिल सके; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कानूनी उपबन्ध क्या हैं?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख). जांच आयोग अधिनियम, 1952 की वर्तमान धारा 10-क के अधीन आयोग अथवा उसके किसी सदस्य को बदनाम करने के किसी कार्रवाई के लिए दांडिक उपबंध मौजूद हैं।

Strike Notice by Port and Dock Workers in Madras

1258. SHRI M. KALYANSUNDARAM:
SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Port and Dock workers in Madras Port went on a strike on 31st January, 1978; and

(b) if so, what are the details of their demands and what steps were taken by Government to settle the problem?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) Yes. A section of workers stopped work for a few hours.

(b) The stoppage of work was in protest against delay in refunding Compulsory Deposit Scheme amount to the flood affected workers. Following an assurance by the Chairman of the Port Trust that the matter would be taken up with the authorities concerned, the workers resumed work. The amounts lying to the credit of the workers certified as flood affected were refunded by the Central Provident Fund Commissioner on 14-2-1978 and have since been paid to the workers concerned.

राष्ट्रीय पुलिस आयोग का प्रतिवेदन

1259. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय पुलिस आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में सुझाई गई मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?